NAME OF THE NEWSPAPER नई दुनिया DATE: 25 AUG 2012

# बांग्लादेशियों का मुद्दा लेकर चुनाव आयोग पहुंची असम गण परिषद

- मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग की
- प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला

प्रतिभा ज्योति

नई दिल्ली। असम में हुई हालिया जातीय हिंसा के बाद असम गण परिषद ने चुनाव आयोग से देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का नाम मतदाता सूची से हटाने को कहा है। पार्टी का आरोप है कि अन्य राजनीतिक दल जानबूझ कर अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर चुप हैं क्योंकि उनके मतदाता हैं और चुनाव में उन्हें सत्ता में लाने की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पार्टी ने आने वाले चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की मांग की है।

असम गण परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत के नेतृत्व में पार्टी के आठ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस संपत, एचएस ब्रह्मा और नसीम जैदी से मिला। पार्टी के राज्यसभा सांसद कुमार दीपक दास ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सामने यह बात रखी है कि असम में लाखों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं इसलिए उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाए।

सूत्रों ने बताया कि असम गण परिषद ने आयोग को बताया है कि अवैध प्रवासियों का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को बताया है कि ये अप्रवासी न केवल गैर कानूनी ढंग से असम में रह रहे हैं बल्कि वह सामाजिक तनाव का कारण भी बन रहे हैं।

आयोग को बताया गया कि अवैध बांग्लादेशियों ने असम के अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, मणिपुर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी अपने पैर जमा लिए हैं और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। पार्टी ने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि असम सहित अन्य राज्यों में मतदाता सूची बनाने का काम बेहद गंभीरता से होगा और अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोगों का नाम इस सूची में दर्ज नहीं किया जाएगा।

इससे पहले महंत बांग्लादेशियों का मुद्दा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने भी उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री को दिए एक ज्ञापन में महंत ने कहा कि गृह मंत्रालय मानता है कि 82 हजार 585 बांग्लादेशियों के पास जिनके पास वैध दस्तावेज थे वह पिछले तीन साल में गायब हो गए हैं।

परिषद ने मांग की है कि गायब हुए बांग्लादेशियों की खोज के लिए सरकार को टास्क फोर्स बनाना चाहिए और 4,096 किलोमीटर के भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के दायरे में उन्हें ढूंढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि असम गण परिषद पार्टी की स्थापना ही बांग्लादेशियों को भारत से निकालने के मुहिम के तहत हुई है। पार्टी लंबे समय से अवैध बांग्लादेशियों के भारत प्रवास को अपना मुख्य चुनावी एजेंडा बनाए हुए है।